ग्रामीण अर्थव्यवस्था व स्थानीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
पेज 2

RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

वर्ष: 01 अंक: 19 देहरादून, शुक्रवार 28 अगस्त 2026 मूल्य 2 रुपये पृष्ठ: 8 www.aawamindia.com

नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह जल-प्रलय

बचाव के लिए भारत से भेजी गई 11 सदस्यों की स्पेशल टीम

मध्य नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई, क्योंकि बचाव दल बाढ़ प्रभावित इलाकों से शव निकालने का काम कर रहे थे। इस आपदा के बाद लगभग 2,000 लोग लापता हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि हिमालयी देश के आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं। चितवन में सबसे ज्यादा मौतें हुई, जहाँ 233 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 158 शव मिले। अधिकारियों ने नुवाकोट से 51, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धाडिंग से 45, तनाहु से 31 और रसुवा से 13 शव बरामद किए। खोज और बचाव अभियान जारी है क्योंकि अधि कारी लापता लोगों का पता लगाने और बाढ़ से हुई तबाही के पूरे पैमाने का आकलन करने के लिए काम कर रहे हैं।

बचाव और राहत कार्यों के तेज होने के साथ ही, स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए 11 सदस्यों वाली एक भारतीय टीम नेपाल पहुँची है। नेपाल सरकार के अनुरोध पर भेजी गई इस टीम में मेडिकल स्टाफ और टनल रेस्क्यू (सुरंग से बचाव) के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चल रहे कार्यों में मदद करेंगे। यह टीम उन इलाकों में राहत कार्यों में मदद करेगी जो अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और

जहाँ अधिकारी बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं।

मध्य नेपाल में तबाही का मंजर; 2,500 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी

बुधवार को रासुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और घरों, सड़कों, पुलों और पनबिजली के बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा। नेपाल और तिब्बत (जहाँ से यह आपदा शुरू हुई) में लगभग 2,500 लोगों के लापता होने की भी खबर है। मुश्किल रास्तों और खराब मौसम के बावजूद बचाव दल प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।

नेपाल विदेशी मदद लेने को तैयार

हिमालयी देश नेपाल ने शनिवार को खोज और बचाव कार्यों के लिए विदेशी मदद लेने की मंजूरी दे दी। जिन देशों के नागरिक लापता हैं, उनके बढ़ते दबाव के कारण नेपाल ने अपना पिछला फैसला बदल दिया। द काठमांडू पोस्ट ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से हम पर जबरदस्त दबाव था कि कम से कम खोज-बचाव टीमों और कुछ विशेषज्ञों को आने की इजाजत दी जाए, क्योंकि बाढ़ में उनके नागरिक भी लापता हो गए हैं।

अधिकारी ने आगे कहा कि नेपाल कुछ खास इलाकों में सीमित संख्या में विदेशी विशेषज्ञों को काम करने की इजाजत देगा। इससे पहले नेपाली सरकार ने विदेशी बचाव टीमों को तैनात करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों को संभालने के लिए उसके अपने सुरक्षा बल और अधिकारी सक्षम हैं।

नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह जल-प्रलय के चार दिन बाद चीनी बचाव दल किसी तरह दुर्गम पहाड़ियों और चट्टानों को पार कर ग्यिरोंग इमिग्रेशन सेंटर तक पहुँचने में सफल रहा। हालांकि, वहाँ पहुँचे रेस्क्यू दल को इमारत की जगह केवल श्मलबे और कीचड़ का ढेर मिला। यह वही इमिग्रेशन सेंटर है जहाँ कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए दर्जनों भारतीय तीर्थयात्री और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की 80 सदस्यों वाली टीम बाढ़ के समय मौजूद थी। 25 अगस्त को आई इस आपदा में अब तक 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 2,000 लोग अब भी लापता हैं।

हालांकि, तिब्बत में बीजिंग के सेंसर ने तुरंत कार्रवाई की, और वीडियो पलक झपकते ही उनके सोशल मीडिया से गायब हो गया। सरकारी मुख्य समाचार बुलेटिन में अब तक वायरल वीडियो का केवल एक फ्रेम ही दिखाया गया है।

यह कोई नई बात नहीं है कि सेंसरशिप के मामले में चीन बहुत सख्त है। उनके इंटरनेट पर केवल सरकार द्वारा मंजूर किए गए विजुअल्स और जानकारी ही जारी की जाती है। अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेपाल में मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है और इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। और फिर भी, चीन ने शुक्रवार को कहा कि अब तक केवल पांच लोगों की मौत हुई है, और 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बहनों का जताया आभार, रक्षा बन्धन की दी शुभकामनाएं

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेशभर से आई बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा तथा उनके

स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने बहनों का आत्मीयता से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और सभी प्रदेशवासियों को रक्षा बन्धन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बन्धन भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पावन पर्व है। प्रदेश की मातृशक्ति और बहनों का स्नेह एवं आशीर्वाद उन्हें उत्तराखण्ड की सेवा तथा राज्य के विकास के लिए निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति परिवार की मजबूत आधारशिला होने के साथ ही समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोकसभा और राज्य विध नसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावध न किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं और बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण और स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के साथ ही उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लखपति दीदी की परिकल्पना को उत्तराखण्ड में तेजी से ध रातल पर उतारा गया है और प्रदेश में 3 लाख 09 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय उत्पादों, कृषि, हस्तशिल्प और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत करने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की मातृशक्ति ने राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कृषि, स्वरोजगार, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी से ही सशक्त उत्तराखण्ड और विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। इस अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर ध ामी, विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती आशा नौटियाल, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रुचि भट्ट एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आई मातृशक्ति मौजूद थी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था व स्थानीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। सूबे में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने आज 'उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026' को मंजूरी दे ही है। इस नीति का उद्देश प्रदेश में सहकारिता आधारित को केवल ऋण वितरण की व्यवस्था तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमिता की मजबूती के लिये विशेष प्रबंध किये गये हैं।

सात रणनीतिक स्तंभों पर आधारित होगी नई सहकारी व्यवस्था

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति-2026 को सात प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। इनमें सहकारिता की बुनियाद को मजबूत करना, सहकारी संस्थाओं की जीवंतता, भविष्य के लिए तैयारी, समावेशिता एवं पहुंच का विस्तार, नए एवं उभरते क्षेत्रों में प्रवेश, सहकारिता से युवा पीढ़ी को जोड़ना तथा आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण प्रमुख हैं।

ग्रामीण विकास, स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। सात रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित यह नीति गांव-गांव में सहकारिता को बढ़ावा देने को व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 की मूल भावना "सहकार से समृद्धि" को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की सहकारिता नीति को तैयार किया गया है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी एवं सीमांत जोतें, बिखरी ग्रामीण आबादी, पलायन, सीमित औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा दुर्गम क्षेत्रों में सेवाओं की सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखा गया। नई नीति में सहकारिता

पैक्स बनेंगे बहुउद्देशीय ग्रामीण आर्थिक केंद्र

नई नीति के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स को केवल ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय, आत्मनिर्भर और व्यावसायिक ग्रामीण आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनके माध्यम से कृषि उद्यान, डेयरी, बागवानी, मत्स्य, भंडारण, कोल्ड-चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, कृषि यंत्र किराया, बीमा, पेंशन, डिजिटल बैंकिंग और अन्य ग्रामीण सेवाओं को सहकारी नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके अलावा हिमालयी उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए छोटे सहकारी उद्यमों को क्लस्टर मॉडल से जोड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा।

सहकारिता में मिलेगा महिलाओं व युवाओं को नेतृत्व का अवसर

नीति में महिला और युवा भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक जनपद में महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने, स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत ऋण एवं बाजार से जोड़ने तथा युवाओं के लिए सहकारी स्टार्टअप, इंटर्नशिप, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा तय की गई है। सहकारिता को युवाओं के लिए सम्मानजनक एवं आकर्षक करियर विकल्प बनाने के लिए प्रशिक्षण, शोध, प्रबंधन एवं आधुनिक कौशल विकास तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य में सहकारिता का होगा विस्तार

नई नीति सहकारिता को पारंपरिक कृषि और ऋण व्यवस्था से आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अंतर्गत सहकारी पर्यटन, होम-स्टे नेटवर्क, इको-टूरिज्म, एग्रो-टूरिज्म, आयुष, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कार्बन क्रेडिट, वन आधारित उत्पाद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य सेवाएं, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल विकसित किए जाएंगे। राज्य-विशिष्ट पहल के रूप में "सहकार टैक्सी" के माध्यम से सदस्य-स्वामित्व वाली परिवहन सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की दिशा भी नीति में शामिल की गई है।

रोजगार व पलायन रोकने पर विशेष जोर

बाइब्रेंट विपेज प्रोग्राम को सहकारिता से जोड़ते हुए सीमांत एवं पर्वतीय गांवों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य गांव में उत्पादित वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सहकारी सेवाओं की पहुंच को भी मजबूत किया जाएगा।

डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक होगी सहकारी व्यवस्थानीति के तहत सहकारी संस्थाओं में कागजरहित कार्यप्रणाली, रियल-टाइम लेखांकन, डिजिटल बैंकिंग, नियमित वित्तीय एवं सामाजिक ऑडिट, पेशेवर प्रबंधन और डिजिटल निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिला सहकारी बैंकों में क्लाउड सीबीएस, पैक्स व बैंक एकीकरण तथा मोबाइल-फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

2026 से 2036 तक तीन चरणों में लागू होगा रोडमैपउत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति-2026 का क्रियान्वयन वर्ष 2026 से 2036 तक तीन चरणों में प्रस्तावित है। पहला चरण के तहत वर्ष 2026-27 तक विधिक सुधार, एमआईएस प्रशिक्षण, संस्थागत ढांचे और डिजिटलीकरण पर फोकस रहेगा। द्वितीय चरण में वर्ष 2028-31 तक ग्राम पंचायत स्तर तक सहकारी सेवाओं का विस्तार, मूल्य-श्रृंखला आधारित क्लस्टर तथा बहुउद्देशीय सहकारी सेवा नेटवर्क का विकास किया जायेगा। तीसरे चरण में वर्ष 2032-36 तक उत्तराखण्ड को पर्वतीय सहकारी उद्यमों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना तथा औषधीय उत्पाद, हस्तशिल्प, दुग्ध, मत्स्य एवं अन्य हिमालयी उत्पादों की राष्ट्रीय और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना है। नीति के माध्यम से राज्य में सशक्त एमपैक्स नेटवर्क, डिजिटल सहकारी इकोसिस्टम, महिला एवं युवा नेतृत्व में वृद्धि, सीमांत क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पलायन में कमी और सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था के साथ डिजिटल डैशबोर्ड आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी। डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड ने कहा की राज्य कैबिनेट ने उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। हमारा लक्ष्य केवल सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और सदस्य-केंद्रित संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ उत्तराखण्ड अपने विशिष्ट 'हिमालयी सहकारिता मॉडल' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

पीएमजीएसवाई की पुरानी सड़कों के सुधार एवं स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी हुई चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेशभर की सड़कों की स्थिति और उनके सुधार के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़कों को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ऐसी पुरानी सड़कों, जिनकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है और जिनका नियमित रखरखाव नहीं हो पा रहा है, को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में सड़क सुधार के कार्य एक साथ युद्धस्तर पर शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग अभी से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करते हुए निविदा प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें, ताकि बारिश समाप्त होने के बाद निर्माण एवं मरम्मत कार्य शुरू करने में किसी प्रकार का विलंब न हो।

बैठक में शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को सड़क सुधार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि शहरी क्षेत्रों की सड़कों को भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अक्टूबर माह से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सड़कों के सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध रूप से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर और सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।

जनपद में पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों को विकसित के दिए निर्देश

संवाददाता

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने मंगलवार को जिला पर्यटन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्थाओं, कार्यप्रणाली तथा पर्यटन कार्यालय भवन एवं परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में संचालित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का भी जायजा लिया और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पंजीकरण केंद्र पर यात्रियों के पंजीकरण व्यवस्था की जानकारी ली साथ ही जिलाधिकारी ने पर्यटन कार्यालय भवन एवं परिसर की साफ-सफाई, रखरखाव, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सूचना पट्टों तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाए रखा जाए तथा यात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर एवं सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंइस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल से जनपद हरिद्वार में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार तथा विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनपद के पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों को और अधिक विकसित एवं आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाए तथा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना एवं पर्यटन विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्थानीय युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे पर्यटन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि हरिद्वार में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की प्रमुख आस्था एवं पर्यटन नगरी है। इसलिए पर्यटन विभाग की योजनाओं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

खेल महाकुम्भ-2026 की तैयारियां तेज, प्रतियोगिताओ को समयबद्ध कराने के निर्देश

रुद्रप्रयाग। खेल महाकुम्भ-2026 के सफल आयोजन को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताओं और विधायक चौम्पियनशिप ट्रॉफी के आयोजन के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। खेल महाकुम्भ-2026 मुख्यमंत्री चौम्पियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ 1 सितम्बर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चम्पावत की मोहनपुर न्याय पंचायत से प्रस्तावित है। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है, जबकि विधायक चौम्पियनशिप ट्रॉफी के आयोजन के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। जिला अधिकारी विशाल मिश्रा द्वारा अधिकारियों को प्रतियोगिताओं की तैयारियां पूरी करने, अधिकाधिक छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण कराने निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभागियों का पंजीकरण ीमसवना.पद/तमहपेजतंजपवद के माध्यम से किया जाएगा।

राज्य स्थापना दिवस 09 नवम्बर तक रोपवे परियोजनाओं के कार्य धरातल पर दिखें : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस 09 नवम्बर तक रोपवे परियोजनाओं के कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को 15 दिन के भीतर रोपवे परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इन परियोजनाओं की प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब स्वीकार्य नहीं होगा और निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें तथा कार्यदायी संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखें। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि, वन भूमि हस्तांतरण, विभागीय स्वीकृतियों अथवा अन्य स्तर पर जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय से त्वरित

कार्रवाई सुनिश्चित करें।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे कनेक्टिविटी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुगम होने के साथ सड़क मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। रोपवे परियोजनाओं से पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (छभ्स्डर), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम (न्ज्ञडत्ब) तथा पर्यटन विभाग से संबंधित विभिन्न रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रस्तुतीकरण के अनुसार प्रथम चरण में छभ्स्डर की 11 तथा द्वितीय चरण में 06 प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं के साथ न्ज्ञडत्ब से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनसे संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रस्तुतीकरण के अनुसार केदारनाथ रोपवे परियोजना की लंबाई 12.90 किमी तथा हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना की लंबाई 12.40 किमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन से श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम होगी। मुख्यमंत्री ने नैनीताल रोपवे परियोजना से संबंधित कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि नैनीताल राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में रोपवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने परियोजना से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी में विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान यातायात का अत्यधिक दबाव रहता है।

रोपवे से पर्यटकों को वैकल्पिक एवं सुगम परिवहन सुविधा मिलने के साथ सड़क यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री, पूर्णागिरि और कुंजापुरी सहित अन्य प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। जिन मामलों में भूमि अथवा अन्य विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, संबंधित जिलाधिकारी उनमें प्रभावी समन्वय स्थापित कर तेजी से समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में हरिद्वार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना तथा त्रिवेणी घाट-नीलकंठ रोपवे से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं में यात्रियों की सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोपवे परियोजनाओं में प्रगति केवल प्रक्रियाओं तक सीमित न रहे, बल्कि 09 नवम्बर तक कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

उन्होंने संबंधित विभागों, जिलाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय से सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान करते हुए परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 15 दिन में मुख्य सचिव को दी जाने वाली प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जल्द ही रोपवे परियोजनाओं की पुनः समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री धीराज गर्ब्याल, कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अतिक्रमण पर कड़ा रुख, अधिकारियों को फील्ड में उतारा

देहरादून। आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे 140 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष प्रकरणों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निश्चित समयावधि के भीतर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए गए। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से भूमि अतिक्रमण, नाला बंद होने से जलभराव, विधवा पेंशन में ठगी, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और विकास कार्यों में देरी से जुड़े मामले छाए रहे।

अतिक्रमण पर कड़ा रुख, अधिकारियों को फील्ड में उतारा

ग्राम पंचायत छरबा (लांघा रोड इंडस्ट्रियल एरिया) में मेसर्स हैब फार्मास्युटिकल एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा बरसाती नाले व ग्राम समाज की भूमि पर दीवार बनाकर जलभराव उत्पन्न करने तथा बबली देवी की जमीन के दो खसरा नंबरों पर अवैध कब्जे की शिकायत का जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने तहसीलदार विकासनगर और प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को बैठक से सीधे मौका मुआयना करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम लक्ष्मीपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को तुरंत जांच कर अतिक्रमण ध्वस्त करने को कहा गया।

पेंशन के नाम पर वसूली और ठगी पर पुलिस जांच

देवऋषि कॉलोनी निवासी जूली की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। आरोप है कि सीएससी सेंटर संचालक ने विधवा पेंशन बनवाने के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे और 4 हजार रुपये लेने के बाद भी उनके मूल दस्तावेज दबाकर बैठ गया। डीएम ने तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी और कोतवाली प्रभारी को संयुक्त रूप से जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।सामाजिक व पारिवारिक उत्पीड़न पर त्वरित कार्रवाई

ऋषिकेश निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला राधारानी द्वारा बहू-बेटे पर मारपीट करने, घर से निकालने और भरण-पोषण न देने के आरोप पर डीएम ने सीओ ऋषिकेश व महिला आयोग की टीम को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। सीमाद्वार निवासी नीमा टोलिया की सास व ननद द्वारा पति की मृत्यु के बाद संपत्ति हड़पने और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न करने के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर निधिक सहायता देने के निर्देश दिए गए। दो छोटे बच्चों के पिता की शिकायत पर, जिसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है और पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही, सीओ को मामले में तेजी लाने को कहा गया। लखवाड़ बांध प्रभावित ग्राम पंचायत की तकनीकी चूक से मुआवजे से वंचित किसानों की समस्या पर एसएलएओ को निस्तारण का जिम्मा सौंपा गया। पांववाला सौड़ा में वित्तीय स्वीकृति न मिलने से अटकी सड़क के लिए लोनिवि के अधिशासी अभियंता और बाला जी विहार में सिंचाई नाले से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग व वन विभाग को कार्य शुरू करने के निर्देश मिले। मोहब्बेवाला में स्पायर स्पोर्ट्स अकादमी में काम करने वाले कर्मचारी की करंट से हुई संदिग्ध मृत्यु मामले में ईई यूपीसीएल को जांच सौंपी गई।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता न मानते हुए प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को समाधान का लाभ मिले और अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करें। समाधान दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी जीतेन्द्र कुमार सहित विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से समस्त उप जिलाधिकारी मौजूद थे।

त्यौहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

देहरादून। त्यौहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों, विशेषकर मिठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम तथा आमजन को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक अभियान शुरू किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा मिलावटखोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके अनुपालन में जिला प्रशासान ने छोटे-बड़े सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर समान रूप से निगरानी रखी जा रही है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा गुणवत्ता से संबंधित शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों एवं डेयरी प्रतिष्ठानों कैन्टीन, रेस्टोरेंट पर छापेमारी एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। टीम द्वारा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई, रख-रखाव एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का जायजा लेते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिन्हें नियमानुसार जांच के लिए भेजा जा रहा है। अभियान के तहत आनंदम स्वीट्स, 5 स्टार, कोहली स्वीट्स, कालरा स्वीट्स सहित अन्य बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों एवं डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान मिठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्री के नमूने संकलित किए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग एवं निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रखा जाए तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि त्यौहारी सीजन में खाद्य सामग्री एवं मिठाइयां खरीदते समय गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्यौहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

सम्पादकीय

दर्द के निशां छोड़ जाता है सैलाब

एक दिन हम नदियों के किनारे आते हैं। शांत मद्धम बहता हुआ वो नीला-हरा पानी लुभाता है। अपने करीब और बहुत करीब हमें बसाता है और फिर एक दिन नदी अपना रूप बदलती है और वो शांत मद्धम बहता हुआ नीला-हरा पानी भयानक सैलाब बन जाता है। वो सैलाब अपने साथ सारी बसावट बहा ले जाता है। सड़कें, घर, पुल और जिंदगी उसके आगोश में समा जाती है और पीछे रह जाता है, कीचड़, बर्बादी और कभी ना भरने वाला खालीपन। आज नेपाल की आपदा की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो तबाही और दर्द के निशां के सिवां कुछ नहीं हैं। वो सैलाब हमें अहसास करा रहा है कि इंसान की सारी तरक्की, सारी तकनीक और सारी ताकत कितनी छोटी हैं।

दरअसल हिमालय जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी है। साल दर साल नेपाल हो या भारत हिमालयी क्षेत्र के पूरे भूभाग में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं में तेजी आयी है। नदियों के किनारे बढ़ती बसावट, जलवायु परिवर्तन, ग्लैशियर का कमजोर होना कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो हैं लेकिन मेरा मानना है कि उससे कहीं ज्यादा हमारी नासमझी है। हम हिमालय को समझ ही नहीं पाये हैं। आपदा आती हैं और कुछ ही दिनों में हम भूल जाते हैं और पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। विकास और पर्यावरण का क्या संतुलन होना चाहिए हम जानते ही नहीं हैं। हम खूबसूरत प्रकृति का आनंद लेने में इतने खो जाते हैं कि सीमा पार कर देते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि प्रकृति नाराज हो जाती है, रोद्र हो जाती है और अहसास करा देती है कि ये सीमा थी, इससे आगे नहीं बढ़ना था। ये हमारी नासमझी है कि हम उस चेतावनी को नहीं समझ पाते हैं।

मेरा मानना है कि हिमालय को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। पहाड़ में विकास जरूरी है। सड़कें, पुल, पर्यटन और रोजगार सब जरूरी है। लेकिन विकास ऐसा हो जो पहाड़ को साथ लेकर चले। एक पैमाना तय हो, एक सीमा तय हो, सुरक्षा के मानक तय हो और आपदा में रिस्पांस टाइम भी तय हो। नेपाल में आई आपदा को केवल एक प्राकृतिक त्रासदी मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। हमें सीखना होगा कि हर आपदा अपने पीछे एक सबक छोड़ती है। ये हमारी भूल है कि हम अक्सर आपदा के समय जागते हैं और खतरा गुजरते ही फिर सो जाते हैं। जब पानी घरों में घुसता है तब हमें नदियां याद आती हैं। जब पहाड़ टूटता है तब हमें जंगल याद आते हैं। जब पुल बहता है तब हमें निर्माण की गुणवत्ता याद आती है और जान दांव पर लगती है तो हमें आपदा प्रबंधन याद आता है।

इन सबसे ज्यादा हमें स्वयं संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सुदूर गांवों की चौपाल तक स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। समय रहते चेतावनी पहुंचानी होगी। सुरक्षित स्थानों की पहचान करनी होगी। स्कूलों और गांवों में नियमित आपदा अभ्यास होना चाहिए। राहत सामग्री संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास उपलब्ध होनी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन ने चुनौती को और गंभीर बना दिया है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। बारिश के पैटर्न में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं लंबे सूखे की स्थिति बन रही है। हिमालय जैसे नाजुक क्षेत्र में इन बदलावों का असर और गहरा हो रहा है। कई ऐसी झील हैं जो आपदा के मुहाने पर हैं। रैंणी, धराली, केदारनाथ, कश्मीर, नेपाल और सैकड़ों क्षेत्र इन दर्द से रूबरू हो चुके हैं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो ऐसा हमें प्रयास करना होगा। साथ ही इंसानियत को भी जिंदा रखना होगा। नेपाल आपदा के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी आयी जो विचलित करने वाली थी। लोग मृतकों के शरीर से सोना नोच रहे थे। बहुत वीभत्स करने वाली वीडियो थी। क्या मानवता का कोई मोल नहीं है। क्या इंसान इतना गिर चुका है कि इंसान के मरने-जीने से कोई प्रभाव ना पड़ता हो। आंखों में आंसू आने के लिए किसी अपने की तकलीफ ही मायने रखती है क्या। हजारों लोग अपने लोगों की तलाश में नदी के उतरते सैलाब के मुहाने पर खड़े हैं। उम्मीदें बुझ चुकी है लेकिन आंखों में आज भी इंतेजार है। सैकड़ों लोग मर चुके हैं। मार्चरी में जगह नहीं है। हजारों लोग लापता है, यदि ऐसी में भी हम में इंसानियत ना जगे तो माफ कीजियेगा हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। सैलाब आते हैं चले जाते हैं लेकिन पीछे जो दर्द के निशां छोड़ जाते हैं हमें उन निशां से सबक सीखना होगा। यदि इंसानियत का भी तकाजा है और जिम्मेदार नागरिक का भी।

बंटवारा एक दिन में लिया गया फैसला न था

भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक दिन में लिया गया फैसला न था। ये उस सियासी शतरंज का आखिरी दांव था, जो पिछले कई साल से चल रही थी। इसकी बिसात पर पिटने वाली थी बेबस आम जनता। जो बदहवासों की तरह इधर उधर भाग रही थी। बंटवारे का खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना को बताया जाता है। इससे ऐतराज भी शायद ही किसी को होगा। लेकिन, कहानी का दूसरा पहलू भी था। कांग्रेस लंबे समय तक अखंड भारत की बात करती रही, लेकिन आखिर में बंटवारा स्वीकार कर लिया। बीच में महात्मा गांधी थे, जो हमेशा कहते थे कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा। सरदार पटेल भी थे और नेहरू भी... हर कोई बंटवारे के सवाल को अलग-अलग नजर से देख रहे थे। जिन्ना हमेशा से बंटवारे के हक में नहीं थे। कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते। 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में उनकी अहम भूमिका थी। सरोजिनी नायडू ने उन्हें कभी शहिंदू-मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा। लेकिन वक्त के साथ जिन्ना को लगने लगा कि आजाद भारत में मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद हिंदुओं के मुकाबले कम रहेगी। कांग्रेस खुद को पूरे भारत की प्रतिनिधि पार्टी मानती थी। जिन्ना इस दावे को स्वीकार नहीं करते थे। उनके लिए मुस्लिम लीग को मुसलमानों का अलग राजनीतिक प्रतिनिधि मानना जरूरी था। 1937 के चुनावों के बाद यह दूरी और बढ़ गई। कांग्रेस कई प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही। मुस्लिम लीग को वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी जिन्ना चाहते थे। यहां से जिन्ना की सोच और पक्की हो गई कि संयुक्त भारत में मुसलमान कमजोर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी वोटिंग पावर कम रहेगी। यहीं से उन्होंने मुस्लिम लीग को एक बड़े मुस्लिम राजनीतिक मंच में बदलने की मुहिम तेज कर दी। फिर 1940 आया। 23 मार्च को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। यहां वह प्रस्ताव पास हुआ जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए अलग राजनीतिक व्यवस्था की मांग रखी गई। पाकिस्तान शब्द प्रस्ताव में नहीं था, लेकिन दिशा साफ हो चुकी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शुरुआत में जिन्ना देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, करीब 1940 तक। वो अलग मुल्क की मांग को बस मोलभाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। उनका इरादा आजादी के बाद एक कमजोर केंद्रीय सत्ता वाला देश था। इसमें मुस्लिमों के लिए वो अलग व्यवस्था और ज्यादा ताकत के हिमायती थे। शायद कुछ आरक्षण जैसी व्यवस्था। जिन्ना की इसी सोच की झलक 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान से भी मिलती है। उन्होंने ऐसे ढांचे को स्वीकार किया था जिसमें भारत ढीला-ढाला संघ रहता। केंद्र सरकार के पास सिर्फ रक्षा, विदेश नीति और संचार होते। बाकी लगभग सारे अधिकार प्रांतों और उनके ग्रुप के पास रहते। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था। जिन्ना को लगता था कि ये व्यवस्था मुस्लिम-बहुल प्रांतों को इतनी स्वायत्तता दे देगी कि भविष्य में वे लगभग पाकिस्तान जैसी स्थिति हासिल कर लेंगे। उन्होंने एक निजी पत्र में लिखा भी था कि पहले ग्रुप बन जाने दें, उसके बाद आगे का रास्ता खुल जाएगा।

लेकिन, शायद कांग्रेस और उसके नेताओं ने जिन्ना की चालाकी को भांप लिया। 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान सभा किसी योजना से बंधी नहीं होगी और उसमें बदलाव कर सकती है। जिन्ना ने इसे कैबिनेट मिशन प्लान की मूल भावना के खिलाफ माना। इसके बाद मुस्लिम लीग ने योजना से समर्थन वापस ले लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को श्डायरेक्ट एक्शनश का ऐलान किया। जिन्ना ने साफ कहा, "अब हम या तो हमारे पास बंटा हुआ भारत होगा, या फिर बर्बाद भारत।" जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का मकसद अलग मुल्क के लिए दबाव बनाना था। यहीं से देश में दंगे भड़क गए। सबसे बुरी तरह झुलसा बंगाल। बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच भीषण हिंसा हुई। कलकत्ता में चार दिनों तक हत्या, आगजनी और लूटपाट चलती रही। इसमें कितने लोग मारे गए, इसका कोई सटीक अनुमान नहीं है। मगर, ज्यादातर इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 4,000 लोग मारे गए। 10,000 से 15,000 लोग घायल हुए। करीब एक लाख लोग बेघर हुए। कलकत्ता के दंगों के बाद हिंसा की सिलसिला शुरू हो गया। अक्टूबर 1946 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज बांग्लादेश में नोआखाली में हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। गावों को जलाया गया। महिलाओं पर जुल्म हुए। जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। महात्मा गांधी खुद नोआखाली पहुंचे। वो गांव-गांव घूमकर माहौल सुधारने की कोशिश कर रहे थे। इसके जवाब में बिहार में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। यहां भी गांव जलाए गए। हजारों मुसलमान मारे गए। फिर पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क गई। यहां हिंदू-सिख-मुस्लिम तीनों समुदाय के लोग निशाना बने। शायद ही कोई बड़ा इलाका बचा होगा, जहां हिंदू-मुस्लिमों के बीच हिंसा न हुई होगी। अब भारत का विभाजन कोई विकल्प नहीं रहा, वो एकदम से अनिवार्य बन गया। फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने लुई माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया। उनका स्पष्ट मिशन था... भारत में ब्रिटिश हुकूमत खत्म करना और सत्ता का हस्तांतरण कराना। वैसे माउंटबेटन को भारत भेजने का फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं था।

श्री नित्यानंद स्वामी स्मृति वन में वृहद पौधारोपण अभियान, 250 पौधों का रोपण

देहरादून। पर्यावरण संरक्षण और युवाओं में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज श्री नित्यानंद स्वामी स्मृति वन, देहरादून में जय युवा संगठन, श्री नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति (पंजीकृत) द्वारा वाईआई -यंग इंडियंस, देहरादून अध्याय के सहयोग तथा उत्तराखंड वन विभाग के सहयोगात्मक समर्थन से वृहद पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 250 पौधों का रोपण किया। अभियान में वैंटेज हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल, द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून, दून इंटरनेशनल स्कूल रिवरसाइड परिसर, तुलाज इंटरनेशनल स्कूल तथा तुलाज संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सहभागिता की। जय युवा संगठन पिछले चार वर्षों से श्री नित्यानंद स्वामी स्मृति वन में निरंतर पौधारोपण अभियान आयोजित करता आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह पहल केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहकर एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकल्प में परिवर्तित हुई है।

संगठन का उद्देश्य आने वाले वर्षों में नियमित पौधारोपण, संरक्षण और देखभाल के माध्यम से इस क्षेत्र को धीरे-धीरे एक समृद्ध एवं सघन वन क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर जय युवा संगठन के अध्यक्ष विनायक शर्मा स्वामी ने कहा कि पौधारोपण का वास्तविक उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं, बल्कि उसके वृक्ष बनने तक उसकी जिम्मेदारी निभाना है। उन्होंने कहा, "एक पौधा लगाना शुरुआत है, पर्यावरण संरक्षण की असली जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाए गए पौधे सुरक्षित रहें, उनका संरक्षण हो और वे आने वाले वर्षों में स्वस्थ वृक्षों के रूप में विकसित हों।"

देहरादून में व्यवस्था सुधारने की बड़ी पहल: अपात्रों के हटेंगे राशन व आयुष्मान कार्ड

देहरादून। राजधानी में नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने और व्यवस्थाओं को

चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की पृथक टास्क फोर्स का गठन किया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी टास्क फोर्स दैनिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और संबंधित विभाग प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

रात्रि में हो रही स्ट्रीट लाइटों की निगरानी

जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स को निर्देशित किया है कि वे रात्रि में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति की जांच करें। जहां भी लाइटें खराब या बंद पाई जाएं, उनकी गूगल लोकेशन और फोटो तुरंत संबंधित विभाग को भेजी जाए, ताकि उन्हें तत्काल ठीक किया जा सके।

सड़क के गड्ढे और कचरा स्थलों की मरम्मत

बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल रिपेयर करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा और बिजली चोरी पर शिकंजा

जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्लम और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए संघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपात्रों के हटेंगे राशन व आयुष्मान कार्ड

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (आयुष्मान व राशन कार्ड) का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि वर्तमान में इन योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिह्नित कर उनके नाम तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए।

सीएम हेल्पलाइन की 36 दिन से लंबित शिकायतों पर चेतावनी

जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए।

सीएम हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी जारी की और प्राथमिकता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए।एक्शन टेकन रिपोर्ट दैनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से विभागों को जिन समस्याओं के निस्तारण हेतु एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जा रही है उसको दैनिक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्व सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष व वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

एसआईआर कार्य में पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ करें नोटिसों की सुनवाई: डीएम

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में आज

भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर राज्य में गतिमान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के अंतर्गत मतदाताओं को जारी किए जा रहे नोटिसों एवं उनकी सुनवाई के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर कार्य की प्रगति, अनोमलीज एवं नो-मैपिंग से संबंधित मामलों तथा मतदाताओं को दिए जा रहे नोटिसों की सुनवाई की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बैठक एवं समन्वय बनाए रखें, ताकि एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी सभी संबंधित पक्षों तक समय पर पहुंच सके। उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अनोमलीज अथवा नो-मैपिंग की स्थिति सामने आने पर मतदाताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतदाता आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर अपना पक्ष रख सकते हैं।

अभिलेखों के नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिए कि वे मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया, नोटिस की स्थिति, सुनवाई की प्रक्रिया तथा आवश्यक अभिलेखों के संबंध में स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता को प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक भ्रम अथवा असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने दावे एवं आपत्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को एसआईआर कार्य में पारदर्शिता, शुद्धता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में प्रशासन एवं निर्वाचन तंत्र का सहयोग करें तथा मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटिरहित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा में एसआईआर से संबंधित कार्य पूर्ण करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सीपीआई(एम) से अनंत आकाश, कांग्रेस से डॉ0 जसविन्दर सिंह, आम आदमी पार्टी से कमल राना एवं बहुजन समाज पार्टी से सतेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

देहरादून । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के मार्गदर्शन तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग श्रीमती पायल सिंह की अध्यक्षता में आज जनपद रुद्रप्रयाग के कुंडा दानकोट में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम एवं बच्चों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जन-जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान करना था। जिसके तहत दहेज प्रतिषेध, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम एवं बाल सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए सचिव महोदया श्रीमती पायल सिंह ने कहा कि बच्चों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए अभिभावकों की सजगता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की दिनचर्या, उनकी मित्र मंडली और डिजिटल गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी रखें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना ही उन्हें अपराध और भटकाव से बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर जोर देते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दहेज की मांग करना या किसी भी रूप में घरेलू हिंसा करना कानूनन गंभीर अपराध है। इसके साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम पर चिंता व्यक्त करते हुए ग्रामीणों को अनजान नंबरों से सतर्क रहने, ओटीपी शेयर न करने तथा साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अक्सर लोग न्यायालयी प्रक्रिया के खर्च एवं अधिवक्ताओं की फीस के भय से अन्याय सहते रहते हैं, किन्तु अब आर्थिक अभाव किसी भी गरीब, महिला, वरिष्ठ नागरिक अथवा वंचित वर्ग के व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं रख सकता। डीएलएसए का उद्देश्य प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाना है। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं तथा लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण किया जाता है। इस दौरान आयोजित कानूनी चौपाल में ग्रामीणों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याएँ सचिव के समक्ष रखीं, जिनका मौके पर ही विधिक परामर्श देकर निस्तारण किया गया।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज सहकारी नीति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शहरी विकास, सैनिक कल्याण सहित

विभिन्न विषयों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट में राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025 के अनुरूप राज्य में सहकारिता क्षेत्र के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति, 2026 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स में उल्लिखित वेतनमान रू0 1,44,200-2,18,200 के लिए वेतन लेवल-15 के स्थान पर वेतन लेवल-14 एवं वेतनमान रू0 1,82,200-2,24,100 के लिए वेतन लेवल-16 के स्थान पर वेतन लेवल-15 संशोधित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया। निर्णय लिया गया कि विभागीय पदीय संरचनाओं/सेवा नियमावलियों में उपरोक्तानुसार जहां-जहां वेतन लेवल-15 एवं 16 अंकित है, के स्थान पर क्रमशः वेतन लेवल-14 एवं 15 समझा/पढ़ा जाएगा।

श्री तिवारी ने बताया कि बैठक में उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन सेस हेतु निर्गत अधिसूचना में सेस की छूट को समाप्त किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान कहा गया कि वर्तमान में अधिकांश हाईब्रिड तथा सी०एन०जी० प्रकार के वाहन ही बाजार में प्रचलन में आ रहे हैं। बैठक में जोर देते हुए कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में तथा सी०एन०जी० प्रकार के वाहनों को मोटरयान कर से छूट प्रदान किए जाने पर राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके दृष्टिगत उपरोक्त प्रकार के वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से कराधान में लाया जाना आवश्यक है।

कैबिनेट बैठक में 'उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026' के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया। बताया गया कि उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत सांख्यिकीय संवर्ग के अन्तर्गत सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित किए जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026' के प्रख्यापन का प्रस्ताव है।

जानकारी दी गई कि आम जनमानस को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने और विभागीय स्तर पर विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के दृष्टिगत औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांटस की समयबद्ध एवं पारदर्शी अधिप्राप्ति हेतु उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति प्रकट की है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) नई दिल्ली, भारत सरकार को राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में अवस्थित 65 एकड भूमि में से 01 एकड़ भूमि को 99 वर्ष की लीज (रू0 01) पर दिए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

बैठक में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में अधीनस्थ कारागारों हेतु उप कारापाल के पद पर 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के पदों पर 90 प्रतिशत प्रधान बन्दीरक्षक एवं 10 प्रतिशत महिला बन्दीरक्षक से पदोन्नति कोटा निर्धारित करने के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन पर सहमति प्रदान की गई।

उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 एवं लोकायुक्त अधिनियम (संशोधन) 2014 की धारा 4 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अधीन लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु उपयुक्त नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति (सर्च कमेटी) के कार्यकलापों का निर्धारण नियमावली, 2026 तैयार करने पर कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया।

सम्पूर्ण प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित आबादी क्षेत्रों में भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण किए जाने हेतु 'उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026' को प्रख्यापित करने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया।

बैठक में उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानान्तरण पर भेजने के संबंध में भी निर्णय लिया गया।

सीएम ने की स्थानीय उत्पादों की खरीदारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सशक्त बहना उत्सव के अंतर्गत

स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों से विभिन्न स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आगामी त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को आगे बढ़ाने में सहभागी बनने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की मातृशक्ति द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किए जा रहे उत्पाद हमारी स्थानीय संस्कृति, परंपरा और हुनर की पहचान हैं। इन उत्पादों को खरीदकर हम न केवल स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उनसे जुड़ी महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का समय स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेशवासी त्योहारों पर उपहार एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दें। हमारे द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पाद की प्रत्येक खरीद किसी परिवार की आय बढ़ाने, किसी महिला के स्वरोजगार को मजबूती देने और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक बनती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'वोकल फॉर लोकल' अभियान ने देश में स्थानीय उत्पादों के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया है। राज्य सरकार भी महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पाद खरीदें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और 'वोकल फॉर लोकल' को जन-अभियान बनाने में अपना योगदान दें। स्थानीय उत्पादों को अपनाने से ही आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी।

राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभावी

नियंत्रण बनाए रखने तथा आम जनता को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के माध्यम से कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित विभाग बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनके मूल्यों की नियमित निगरानी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर आम जनता से अधिक मूल्य न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए तथा आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में प्रशासन द्वारा नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण किया जाए। आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित एवं प्रचलित बाजार मूल्यों की जांच के साथ ही स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ता है, इसलिए मूल्य नियंत्रण से संबंधित सभी व्यवस्थाएं प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए बाजार की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

फिल्म दिल से को मणिरत्नम ने लिखा और निर्देशित किया

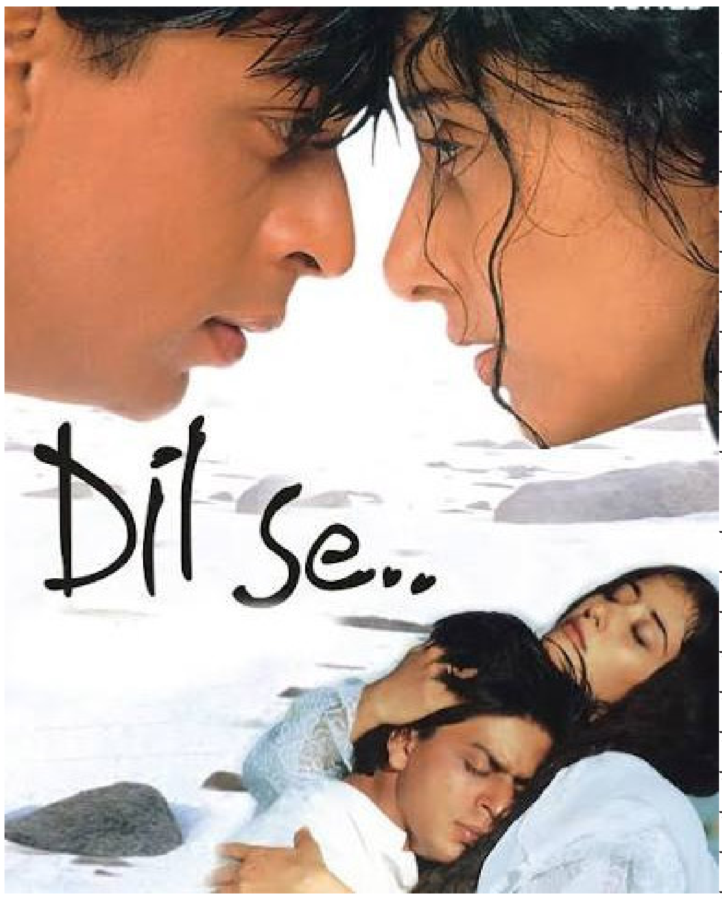

नई दिल्ली। दिल से 1998 में बनी एक भारतीय हिंदी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे मणिरत्नम ने लिखा और निर्देशित किया है। उन्होंने रामगोपाल वर्मा और शेखर कपूर के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है । असम में चल रहे उग्रवाद की पृष्ठभूमि पर आधारितइस फिल्म में शाहरुख खान और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिका में हैं , जबकि प्रीति जिंटा ने सहायक भूमिका में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है। समानांतर सिनेमा का एक उदाहरण मानी जाने वाली यह फिल्म, मणिरत्नम की त्रयी श रोजाश (1992) और श्बॉम्बेश (1995)की अंतिम कड़ी है । एआर रहमान द्वारा संगीतबद्ध फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम कीभारत में छह मिलियन प्रतियां बिकीं। दिल से... को एरा न्यू होराइजन्स फिल्म फेस्टिवल और हेलसिंकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। अपनी गैर-रेखीय कहानी कहने की शैली के लिए जानी जाने वाली यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर औसत रूप से सफल रही; हालाँकि, विदेशों में यह एक बड़ी सफलता थी, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 975,000 और यूनाइटेड किंगडम में 537,930 कमाए, जहाँ यह शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, और यह जापान में भी हिट रही। 44वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में , शदिल से...श को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (कोइराला) और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (जिंटा) सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और इसने सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू (जिंटा) और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक (रहमान) सहित 6 पुरस्कार जीते। 46वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में , फिल्म ने दो पुरस्कार जीते - सर्वश्रेष्ठ छायांकन और सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी , साथ ही 49वें बर्लिनाले में नेटपैक पुरस्कार भी प्राप्त किया ।

अमरकांत ष्अमरष वर्मा नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के एक उत्साही कार्यक्रम कार्यकारी हैं , जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता की आगामी 50वीं वर्षगांठ के संबंध में स्थानीय दृष्टिकोणों पर रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तर-पूर्वी भारत भेजा गया है। हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान फंसे होने पर , उनकी मुलाकात एक रहस्यमय महिला से होती है, जिसकी आकर्षक उपस्थिति उन्हें तुरंत आकर्षित करती है। उनके अनौपचारिक बातचीत के प्रयासों के बावजूद, वह उदासीन और मौन बनी रहती है। जब वह अंतत: एक कप चाय मांगती है, तो अमर पास के एक कियोस्क की ओर दौड़ता है, लेकिन जब वह लौटता है तो देखता है कि वह तीन अज्ञात पुरुषों के साथ एक ट्रेन में सवार हो रही है। अमर सिलचर में अपने कार्य को आगे बढ़ाता है , जहाँ वह क्षेत्रीय नागरिकों और एक उग्रवादी विद्रोही सरदार सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का साक्षात्कार लेता है। सरदार खुले तौर पर भारतीय सरकार और सेना पर व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन और संस्थागत उपेक्षा का आरोप लगाता है, अपने सशस्त्र प्रतिरोध को उचित ठहराता है और राज्य के साथ किसी भी राजनयिक बातचीत से इनकार करता है। अपनी यात्रा के दौरान, अमर को वह रहस्यमयी महिला फिर से दिखाई देती है। जब वह उससे इस बारे में पूछता है, तो वह उनकी पिछली मुलाकात की कोई भी बात याद होने से इनकार करती है। फिर भी, अमर रेडियो पर उनकी मुलाकात का काव्यात्मक वर्णन प्रसारित करता है, जिसे वह सुन लेती है। वह उसका पीछा करते हुए एक स्थानीय डाकघर तक पहुँचता है, उसे घेर लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है। उसकी जिद को रोकने के लिए, वह कहती है कि वह शादीशुदा है। जब पश्चाताप से भरा अमर बाद में अपनी आक्रामकता के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, तो वह उसे एक जाल में फंसा लेती है जहाँ उसके दो साथी उसे पीट-पीटकर बेहोश कर देते हैं। बाद में अमर को पता चलता है कि महिला ने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोला था और अचानक अपना घर खाली कर दिया था। एक सार्वजनिक टेलीफोन ऑपरेटर को रिश्वत देकर, वह पता लगाता है कि वह नियमित रूप से लद्दाख में लंबी दूरी की कॉल कर रही थी ।

अमर सिंधु दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग के बहाने लेह जाता है । अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, वह सैन्य बलों को एक स्थानीय आत्मघाती हमलावर को निष्क्रिय करते हुए देखता है। अफरा-तफरी के बीच, अमर उस महिला को एक सार्वजनिक बस में चढ़ते हुए देखता है। जब सैन्य सुरक्षाकर्मी यात्रियों से पूछताछ करने के लिए वाहन को रोकते हैं, तो महिला अमर की उपस्थिति का फायदा उठाकर, सैनिकों से झूठ बोलकर कि वह उसका पति है, जांच से बच जाती है। जब एक सुनसान इलाके में बस खराब हो जाती है और यात्रियों को पास के एक गाँव तक पैदल जाना पड़ता है, तो अमर मेघना से मिलता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपना नाम मेघना बताए। वे एक दिन साथ यात्रा करते हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर पल साझा करते हैं, लेकिन अगली सुबह अमर उठता है तो पाता है कि मेघना गायब हो गई है। अमर को पता नहीं होता कि मेघना एक चरमपंथी मुक्ति मोर्चे की प्रमुख सदस्य है, जो वर्तमान में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली में सिलसिलेवार आत्मघाती बम विस्फोटों की योजना बना रही है । निराश अमर दिल्ली लौट आता है, जहाँ उसका परिवार केरल की एक जीवंत महिला प्रीति नायर से उसका विवाह तय कर देता है । यह सोचकर कि वह मेघना को फिर कभी नहीं देख पाएगा, अमर इस रिश्ते के लिए राजी हो जाता है। हालांकि, प्रीति के साथ एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, अमर मेघना के एक विद्रोही सहयोगी किम को पहचान लेता है। अमर कनॉट प्लेस में उसका पीछा करता है , लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर, वह साइनाइड की गोली खाकर आत्महत्या कर लेता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले को अपने हाथ में ले लेती है। इसी बीच, मेघना दिल्ली पहुँचती है और चुपके से अमर से दोबारा संपर्क करती है, और उससे अनुरोध करती है कि वह अपने आधिकारिक पहचान पत्रों का उपयोग करके उसके प्रसारण कार्यालय में उसे एक अस्थायी कर्मचारी पद दिलवा दे। अमर मान जाता है, और अनजाने में उसे सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए अपने घर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है।कनॉट प्लेस से प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर, सीबीआई अमर को एक प्रमुख आतंकवादी संदिग्ध मानते हुए निगरानी में रखती है।

27 नवंबर 2023 की वो खौफनाक सुबह! Himanshi Khurana ने Asim Riaz की खोली पोल, बोलीं- अब पर्दा डालने का खेल खत्म

बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना और उनके पूर्व साथी असीम रियाज के बीच का विवाद एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। असीम रियाज द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों के बाद, हिमांशी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और सख्त नोट साझा करते हुए चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अब तक असीम की छवि को बचाने के लिए खामोश थीं, लेकिन बार-बार हो रहे अपमान के बाद अब वे तथ्यों और सबूतों के साथ कानूनी व सार्वजनिक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

23 अगस्त को असीम द्वारा उनके पहले के दावों को गलत बताए जाने के बाद हिमांशी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया। अपने हालिया बयान में, उन्होंने साफ किया कि उन्होंने कभी भी इस स्थिति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला नहीं बताया। उन्होंने लिखा, ष्मैंने कभी नहीं कहा कि श्जबरदस्ती धर्म परिवर्तनश हुआ था। लोगों और मीडिया ने यह नैरेटिव बनाया।ष

हिमांशी का कहना है कि उनके पास धर्म परिवर्तन विवाद से जुड़े सबूत हैं

हिमांशी ने आगे कहा कि अगर बातचीत तथ्यों पर आधारित होगी तो वह सबूत शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस मामले से जुड़े ब्ब्ज्ट फुटेज और रिकॉर्डिंग हैं और उन्होंने 27 नवंबर, 2023 की सुबह का जिक्र किया।

उन्होंने लिखा, श्अगर हम सबूतों की बात करने जा रहे हैं, तो आइए हर चीज पर बात करें। मैं धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले और हाँ, मेरे साथ हुई हिंसा से जुड़े तथ्य और सबूत (ब्ब्ज्ट फुटेज, रिकॉर्डिंग... उम्मीद है आपको 27.11.23 की वह सुबह याद होगी) शेयर करने के लिए तैयार हूँ।श

एक्ट्रेस ने अपनी सेहत का मजाक उड़ाने और अपने संघर्षों पर सवाल उठाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक सीमा तय करना जरूरी लग रहा है।

हिमांशी खुराना का कहना है कि वह अब चुप नहीं रहेंगी

हिमांशी ने आगे आरोप लगाया कि वह पहले असीम की इमेज बचाने के लिए चुप रही थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने लिखा, श्अगर आप मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं, तो अब मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो आपकी तथाकथित इमेज बचाने के लिए पर्दा डालती रहेगी, या बार-बार अपमान और बेइज्जती सहते हुए चुप रहेगी।श

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस और चौनलों से जुड़े लोगों ने असीम के व्यवहार पर पर्दा डाला था। श्अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस और चौनलों के लोगों ने आपकी हरकतों पर पर्दा डाला, लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूँ।श उन्होंने लिखा, श्अगर उस सम्मान का जवाब वैसा ही नहीं मिलता, तो मेरे पास अब चुप रहने की कोई वजह नहीं है।श

हिमांशी सवाल करती हैं कि वह अपनी कहानी क्यों नहीं बता सकतीं। अपने नोट के आखिर में, हिमांशी ने असीम को चुनौती दी कि वे तथ्यों, जवाबदेही और पूरी सच्चाई के साथ इस मामले पर बात करें। उन्होंने लिखा, श्मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब मैं अपनी यात्रा और उससे मिली सीख के बारे में बताती हूँ तो लोगों को क्या परेशानी होती है, जबकि बाकी सब अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते हैं। जब मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ तो यह अलग क्यों होता है?श

हिमांशी और असीम, जो बिग बॉस 13 के दौरान मिले थे, 2023 में अलग होने की घोषणा करने से पहले कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे।

उपराष्ट्रपति ने किया पुस्तक ''संकल्प से सिद्धि का मोदी युग'' का विमोचन

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक ''संकल्प से सिद्धि का मोदी युग'' का विमोचन किया। श्री सीपी राधाकृष्णन ने ''संकल्प से सिद्धि का मोदी युग'' शीर्षक को एक सशक्त और प्रेरणादायक संदेश देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संकल्प मात्र एक इच्छा नहीं, बल्कि समर्पण, परिश्रम और अनुशासन से समर्थित एक दृढ़ निश्चय है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह पुस्तक पिछले बारह वर्षों में भारत की यात्रा का वर्णन करती है। इसमें प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ-साथ वैचारिक पुनर्जागरण भी शामिल है और यह 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना के संदर्भ में प्रस्तुत करती है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, केशव बलिराम हेडगेवार, वीर सावरकर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान राष्ट्रीय विचारकों के विचारों और आदर्शों को समकालीन शासन से जोड़ने के पुस्तक के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि लेखक ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ''सेतु पुरुष'' के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया है- सपनों और वास्तविकता के बीच एक सेतु - यह इन विचारों के संकल्प और समकालीन भारत में उनकी प्राप्ति के बीच सम्बंध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए प्रमुख विकासों को याद करते हुए श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्र प्रथम, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय की भावना को समाहित करती है। उन्होंने राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, महिला नेतृत्व वाला विकास, आत्मनिर्भर भारत और पारदर्शी शासन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यह कृति विभिन्न शासन सम्बंधी पहलों को स्थायी राष्ट्रीय विचारों को क्रियान्वित करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत के साथ-साथ पाठकों को भारत की यात्रा पर चिंतन करने और आत्मविश्वास और आशावाद के साथ भविष्य की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद और लेखक श्री घनश्याम तिवाड़ी, राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह सिरोया और प्रभात प्रकाशन के श्री पवन कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ए. बालकृष्णन के निधन पर पीएम ने जताया शोक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे श्री ए. बालकृष्णन जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधनमंत्री ने श्री बालकृष्णन जी के समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का पांच दशक से अधिक समय स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया।

श्री मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर से उनका विशेष जुड़ाव था। उन्होंने शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा: विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में सेवारत रहे श्री ए. बालकृष्णन जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है।

बालकृष्णन जी ने अपने जीवन का पांच दशकों से अधिक समय स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और समाज सेवा में समर्पित किया। विवेकानंद केंद्र के प्रारंभिक जीवनव्रतियों में से एक के रूप में, उन्होंने पूरे देश में अथक परिश्रम किया। पूर्वोत्तर से उनका विशेष जुड़ाव था। उन्होंने शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विवेकानंद केंद्र के संपूर्ण परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ। ऊँ शांति।

प्रारूप-7 की आपत्तियों का पारदर्शिता के साथ सावधानीपूर्वक निस्तारण करने पर जोर

देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की रैंडम जांच, ऑडिट एवं पर्यवेक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मंगलवार को देहरादून जनपद का भ्रमण किया।

आयोग की टीम ने जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह तथा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। आयोग की टीम ने जनपद में पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ संचालित किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की सराहना की। टीम ने निर्देश दिए कि प्रारूप-7 के अंतर्गत प्राप्त अधिक संख्या में आपत्तियों का अत्यंत सावधानी एवं निष्पक्षता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मृत्यु अथवा स्थानांतरण के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की स्थिति में संबंधित मतदाता की जानकारी का बीएलओ तथा संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (ठस्।) से अनिवार्य रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन कराया जाए। आयोग की टीम ने यह भी बताया कि निर्धारित 11 प्रमाण-पत्रों में से अभी तक कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले मतदाताओं से पुन: संपर्क कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपील की जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आयोग की टीम को जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण में विसंगति पाए जाने अथवा संबंधित विवरण उपलब्ध न कराए जाने के मामले में 21 अगस्त तक बीएलओ के माध्यम से 5,47,617 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत मामलों में सुनवाई पूरी की जा चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 96,187 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनका नाम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं को अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक राज्य की मतदाता सूची में रहने का अवसर दिया जा रहा है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी तथा उनकी स्वेच्छा के आधार पर आगे की कार्वाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राकेश तिवारी, अपर्णा ढौंडियाल, रविन्द्र ज्वांठा, अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद देवली उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान जारी, 12 नमूने जांच के लिए भेजे गए

हरिद्वार। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तराखण्ड विनय शंकर पाण्डेय एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 25 अगस्त 2026 को जनपद हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विभिन्न टीमों द्वारा पनीर एवं मिठाई निर्माण यूनिटों, मिठाई दुकानों एवं डेरियों का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा, गढ़वाल मण्डल आर एस रावत के नेतृत्व में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ, गुप्त सूचना के आधार पर सोहलपुर (कलियर के पास) स्थित मिठाई निर्माण इकाई वाजिद स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। मौके पर आठ जंक लगे एवं गंदे टीन के कनस्तरों में लगभग 1.6 कुंतल सफेद रसगुल्ला, 15 किलो गुलाबी रंग वाले रसगुल्ले, 25 किलो स्टार्च पाउडर तथा लगभग 40 किलो मिल्क केक विक्रय हेतु संग्रहित मिला। रसगुल्लों के कई टीनो में मरी हुई मधुमक्खीया एवं मक्खियाँ मिलीं, कनस्तरों में जंग लगी थी तथा रसगुल्लों में स्टार्च पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। निर्माण स्थल पर बेहद गंदगी पायी गयी जो कि फूड ग्रेड नहीं था, कच्ची फर्श होने तथा साफ-सफाई का अभाव होने के कारण दीवारें एवं छत काली पायी गयीं तथा मिल्क केक की ट्रे एवं डिब्बों को धूल भरे स्थानों में संग्रहित किया गया था। खुला रसगुल्ला व स्टार्च पाउडर के 03 नमूने लेने के उपरान्त शेष मिठाइयों तथा लगभग 2 क्विंटल स्टार्च पाउडर को मौके पर ही गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया गया।

इकाई वाजिद स्वीट्स में मिठाई निर्माण कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया गया है तथा फर्म के एफएसएसएआई लाइसेंस को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है। इसी टीम द्वारा सिडकुल स्थित एक पनीर निर्माण यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर फ्रीजर में लगभग 50 किलो निर्मित पनीर संदिग्ध मिला। यह एनालॉग पनीर है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिये उक्त पनीर में से एक नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया।

मौके पर कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं मिला। उन्होंने अवगत कराया है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा द्वारा मायापुर, कनखल, रानीपुर मोड़ तथा ज्वालापुर स्थित 08 डेयरियों,ढाबों, रेस्टोरेंट व सप्लायर का निरीक्षण किया गया। मौके पर प्रयोगशाला जांच हेतु घेवर मिठाई-01, पतीसा मिठाई-01,खुला दूध -01,पैक्ड दही-01 तथा पैक्ड ऑयल सहित 05 नमूने लिये गये।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia